

>

Title: Regarding uniform education and examination policy.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । कांग्रेस के मॅबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे ही परेशान रहते हैं । इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह शिक्षा की समस्या है । शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, इरीगेशन, ये सब ऐसे विषय हैं, जिसके लिए हम सभी मॅबर ऑफ पार्लियामेंट यहां जीत कर आते हैं और जनता को हम कहते हैं कि इस तरह की सुविधा आपको देंगे । जिस वक्त यह संविधान बन रहा था, उस वक्त कुछ ऐसी बातें हो गईं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, इरीगेशन, ये सब समस्यायें, जो आम लोगों को जोड़ती हैं, वे सब कनकरेंट लिस्ट में चली गईं या स्टेट लिस्ट में चली गईं । हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 3-4 तरह के बोर्ड हो गए हैं । सीबीएसई अलग एग्जाम लेता है, उसके अलग स्कूल्स हैं । आईसीएसई अलग बोर्ड है, वह अलग एग्जाम लेता है । सारे स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, जो अलग-अलग एग्जाम्स लेते हैं । अलग-अलग एग्जाम्स लेने के कारण, उनकी अलग-अलग पढ़ाई होती है । मेरा लैंगुएज से कोई मतलब नहीं है । भारत की जितनी भी भाषायें हैं, उन सारी भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, हम इसके समर्थक हैं । उस एजुकेशन व्यवस्था में ही यदि आप एक जिले में देखेंगे, तो कई जगह प्राइवेट स्कूल हैं, उसी तरह से स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, उसी तरह से सेंट्रल स्कूल्स हैं, जिनमें मॅबर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा है और उसी तरह से नवोदय स्कूल्स चल रहे हैं । केन्द्र सरकार भी स्कूल चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूल चला रही है और प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं । प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अलग फीस है । स्टेट्स में शिक्षा फ्री है । सेंट्रल स्कूल्स की एक अलग फीस है । जो राष्ट्रीय एग्जाम है, जिसको आईएस बनना है, आईपीएस बनना है, जिसको आईआईटी, आईआईएम में जाना है, उसका एक अलग ऑल इंडिया का एग्जाम है ।

आप देखेंगे कि इस कारण ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग कोटा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जहां से आप आते हैं । स्टेट बोर्ड सीबीएसई पैटर्न पर नहीं

पढ़ाता है, आईसीएसई बोर्ड पैटर्न पर नहीं पढ़ाता है, गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है । इस कारण अमीरों के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चे ऑल इंडिया एग्जाम ज्यादा कम्पीट कर पा रहे हैं और रूरल बैकग्राउंड के बच्चे कम कर पा रहे हैं ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, एनसीईआरटी की बुक है क्योंकि बुक भी एक बड़ा स्कैम है । एक सिलेबस, एक एग्जाम और एक देश जैसे एक निशान, एक विधान के लिए धारा 370 का किया, यदि वह लागू करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसमें कम्पीट कर पाएंगे । मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री अजय कुमार, डॉ. संजय जायसवाल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।